बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड संयंत्र का उद्घाटन

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया | यह संयंत्र किसानों को किफायती यूरिया प्रदान करेगा और उनकी उत्पादकता एवं वित्तीय स्थिरता में वृद्धि करेगा।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) उर्वरक संयंत्र 9500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित हुआ | सरकार ने हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) को 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (एलएमटीपीए) की यूरिया उत्पादन क्षमता के साथ 9512 करोड़ रु. के अनुमानित निवेश के साथ बरौनी इकाई को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया था।
- हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) के बरौनी उर्वरक संयंत्र ने अक्टूबर 2022 में यूरिया उत्पादन शुरू किया। अत्याधुनिक गैस आधारित बरौनी संयंत्र, यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की बंद पड़ी यूरिया इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल का हिस्सा है।

हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के बारे में

- 15 जून, 2016 को निगमित की गई हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एनटीपीसी लिमिटेड (एनटीपीसी), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और एफसीआईएल/एचएफसीएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसे अनुमानित तौर पर 25,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी इकाइयों को पुनर्जीवित करने का काम सौंपा गया है।
- एचयूआरएल के सभी तीन संयंत्रों की शुरुआत से देश में 38.1 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (एलएमटीपीए) स्वदेशी यूरिया उत्पादन बढ़ेगा और यूरिया उत्पादन में भारत को 'आत्मनिर्भर' बनाने के प्रधानमंत्री के स्वप्न को साकार करने में सहायता मिलेगी। यह परियोजना न केवल किसानों के लिए उर्वरक की उपलब्धता में सुधार करेगी बल्कि देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा सड़क, रेलवे, सहायक उद्योग आदि जैसे बुनियादी ढांचे के विकास सहित क्षेत्र में भी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी।
- हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) संयंत्र (प्लांट) में विभिन्न अनूठी विशेषताएं हैं जैसे वितरित नियंत्रण प्रणाली (डीसीएस), आपातकालीन शटडाउन प्रणाली (ईएसडी) और पर्यावरण निगरानी प्रणाली आदि से सुसज्जित अत्याधुनिक ब्लास्ट प्रूफ नियंत्रण कक्ष। इसमें 65 मीटर लंबाई और 2 मीटर ऊंचाई का भारत का पहला वायु संचालित बुलेट प्रूफ रबर बांध भी है।
- यह सुविधा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों में यूरिया की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से दुनिया की विश्व प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करती है। यूरिया आपूर्ति के अलावा, यह परियोजना विनिर्माण इकाई अपने आसपास के छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों / विक्रेताओं के विकास में भी मदद करेगी।
- संयंत्रों के संचालन से देश यूरिया उर्वरक के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा, आयात कम होने से विदेशी मुद्रा

की बचत होगी और यह "उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत" की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NUCFDC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NUCFDC) का उद्घाटन किया।

NUCFDC से संबंधित प्रमुख बिंदु

- NUCFDC शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है | यह क्षेत्र के लिए एक स्व-नियामक संगठन के रूप में भी काम करेगा।
- इसका उद्देश्य सहकारी बैंकों के लिए विशेष कार्यों और सेवाओं को सुनिश्चित करना, बैंकों और नियामकों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करना और शहरी सहकारी बैंकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है।
- साथ ही शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत बनाना है, जिससे बैंकों और उनके ग्राहकों दोनों को लाभ होगा।
- इसे गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के बारे में

- यूसीबी को संबंधित राज्य के राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम या बहु राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत किया जाता है।
- उन्हें संबंधित राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) या केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) द्वारा, जैसा भी मामला हो, विनियमित और पर्यवेक्षण किया जाता है।
- वे मुख्य रूप से भारत के शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं।
- ये संस्थाएँ छोटे व्यवसायों, व्यक्तियों और समुदायों की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। सेवाओं में जमा खाते, ऋण, प्रेषण और अन्य वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ शामिल हैं।
- वर्तमान में, भारत में 1,500 से अधिक अनुसूचित और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक हैं।

स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग (SGLR) पहल

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के मढ़ई में स्थित बाइसन रिसॉर्ट्स ने पहले पांच स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग प्रमाणपत्र प्राप्त करके अग्रणी स्थान हासिल किया है। यह सम्मान जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं के प्रति रिसॉर्ट की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और पर्यटन उद्योग के लिए एक सराहनीय मिसाल कायम करता है।

स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग (SGLR) पहल के बारे में

- गौरतलब है कि यह स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग (एसजीएलआर) पहल नवंबर 2023 में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के सहयोग से शुरू की गई थी।
- इसका उद्देश्य होटलों, रिसॉर्ट्स और होमस्टे में विश्व स्तरीय स्वच्छता और स्वच्छता सुनिश्चित करना, जल निकायों में प्रदूषण को रोकना और पर्यावरण को स्वच्छ रखना है।
- जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग (एसजीएलआर) पहल शुरू की है।

- इस पहल का लक्षित समूह होटल, लॉज, होमस्टे, 'धर्मशालाएं' और शिविर हैं जिनमें पोर्टेबल शौचालय हैं। रेटिंग दिशानिर्देशों में उल्लिखित सुरक्षित स्वच्छता प्रथाओं के अनुपालन पर आधारित होगी।
- भारत के बढ़ते पर्यटन उद्योग में स्वच्छता प्रथाओं में बदलाव लाने के लिए यह पहल शुरू की गई है | यह कार्यक्रम पर्यटकों के लिए विश्व स्तरीय साफ-सफाई और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने एवं स्वच्छ और अधिक टिकाऊ पर्यटन प्रथाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- इसका कार्यान्वयन के लिए एक त्रि-स्तरीय समिति प्रणाली प्रस्तावित की गई है, जिसकी शुरुआत जमीनी स्तर पर सत्यापन के लिए उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) द्वारा गठित एक सत्यापन उप-समिति से होगी, इसके बाद एक जिला समिति होगी, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर करेंगे। और फिर राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य-स्तरीय समिति।
- SGLR पहल मिशन लाइफ (एलआईएफई) के तहत ट्रैवल फॉर लाइफ (टीएफएल) कार्यक्रम के अनुरूप है, जो टिकाऊ पर्यटन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देती है। एसजीएलआर कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यटकों और व्यवसायों दोनों को प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए आर्थिक रूप से व्यवहार्य, जिम्मेदार और सुदृढ़ पर्यटन उद्योग विकसित करना है।

राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023

सुर्ख़ियों में क्यों?

- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर 1 मार्च, 2024 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक का पांचवां संस्करण भी जारी किया।

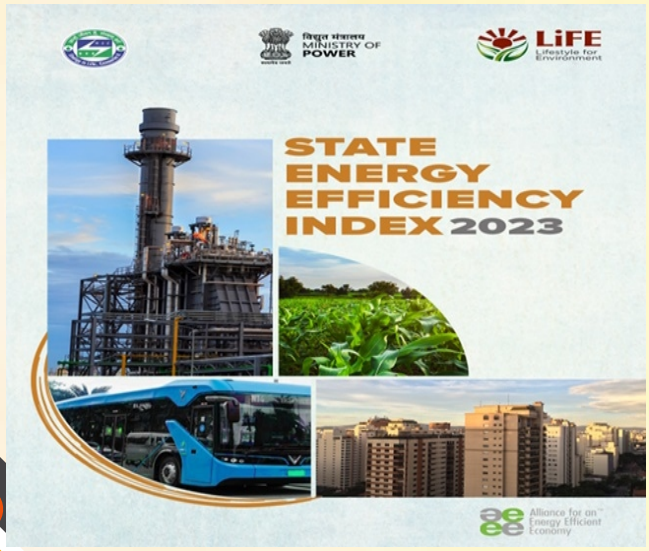

संबंधित प्रमुख बिंदु

- इसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी (एईईई) के सहयोग से शुरू किया है, ताकि राज्यों में ऊर्जा दक्षता कार्यान्वयन की वार्षिक प्रगति आकलन किया जा सके।
- राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (एसईईआई) राज्य-स्तरीय ऊर्जा दक्षता नीतियों, कार्यक्रमों और निवेशों से संबंधित कमियों की पहचान और उनका समाधान करता है।
- यह सात मांग क्षेत्रों में वितरित 65 गुणात्मक, मात्रात्मक और परिणाम-आधारित संकेतक उपायों का उपयोग करके 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करता है।
- एसईईआई 2023 में, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके आधार पर 'फ्रंट रनर' (>=60), 'अचीवर' (50-59.75), 'कंटेंडर' (30-49.75), और 'एस्पिरेंट' (<30) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इसके अलावा, प्रदर्शन की सहकर्मी से सहकर्मी तुलना को सक्षम करने के लिए, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी कुल अंतिम ऊर्जा खपत (टीएफईसी) के आधार पर चार समूहों में वर्गीकृत किया गया है: समूह 1 (>15 मिलियन टन तेल समकक्ष (एमटीओई)), समूह 2 (5 - 1 5 एमटीओई), समूह 3 (1-5 एमटीओई), और समूह 4 (<1 एमटीओई)।
- प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कर्नाटक (समूह 1), आंध्र प्रदेश (समूह 2), असम (समूह 3), और चंडीगढ़ (समूह 4) हैं।
- 100 में से 86.5 के समग्र स्कोर के साथ, कर्नाटक एसईईआई 2023 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है जबकि 83.25 अंक के साथ दूसरा सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है|
- एसईईआई 2023 में, पंद्रह (15) राज्यों ने एसईईआई 2021-22 की तुलना में अपने स्कोर में सुधार किया है। विशेष रूप से, चार राज्यों- गोवा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा ने एसईईआई 2021-22 के सापेक्ष 10 अंकों से अधिक सुधार करते हुए महत्वपूर्ण प्रगति का प्रदर्शन किया है। विशेष रूप से, इस आकलन में सबसे बेहतर राज्य महाराष्ट्र और हरियाणा हैं|

स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 4 मार्च, 2024 को केंद्रीय इस्पात एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयन्त्र का हिसार के जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया।
- यह स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए ऑफ-ग्रिड हरित हाइड्रोजन संयन्त्र और रूफटॉप तथा फ्लोटिंग सोलर वाला दुनिया का पहला हरित हाइड्रोजन संयन्त्र होगा।
- इस परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 2,700 मीट्रिक टन प्रति वर्ष कार्बन उत्सर्जन में कमी के साथ-साथ अगले दो दशकों में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 54,000 टन की कमी आएगी।

हरित हाइड्रोजन (ग्रीन हाइड्रोजन) क्या होता है?

- जब जल से विद्युत धारा गुज़रती है, तो इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से यह मूल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में खंडित हो जाती है। यदि इस प्रक्रिया के लिये उपयोग की जाने वाली विद्युत का स्रोत, पवन या सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोत हैं तो इस प्रकार उत्पादित हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहा जाता है।
- यदि हाइड्रोजन अणु को प्राप्त करने के लिये प्रयुक्त बिजली के स्रोत के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता है, तो इसे 'ब्लैक या ब्राउन' हाइड्रोजन कहा जाता है।
- विदित है कि हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है लेकिन शुद्ध हाइड्रोजन की मात्रा अत्यंत ही कम है। यह लगभग हमेशा ऑक्सीजन के साथ H_2O, अन्य यौगिकों में मौजूद होता है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में

- भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से लगभग 20,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2023 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) लॉन्च किया गया है।
- यह मिशन वित्त वर्ष 2029-30 तक लगभग 500 करोड़ रुपये के बजट के साथ इस्पात क्षेत्र में पायलट परियोजनाओं का भी समर्थन कर रहा है।
- इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत में लगभग 125 GW (गीगावाट) की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने के साथ-साथ प्रतिवर्ष कम-से-कम 5 MMT (मिलियन मीट्रिक टन) की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना है। इसके तहत कुल 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर 6 लाख नौकरियाँ सृजित करना अपेक्षित है।
- इस मिशन का नोडल एजेंसी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है|